



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यपालन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, १७ दिसम्बर, १९९४/२६ ग्रन्थावधि, १९१६

हिमाचल प्रदेश सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

अभिसूचना

शिमला-१७१००२, १७ दिसम्बर, १९९४

संख्या पी० सी० एच०-एच० ए० (४)-१/९४.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद २४३-के० और २४३-जेड० ए० के खण्ड (२) के साथ पठित, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, १९९४ (१९९४ का ४) की धारा १६० और १८६ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा अर्त) नियम, १९९४, जिन्हें पहले ही सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया है, के नाम से निम्न नियम

मनाने के महर्ष आदेण प्रदान करते हैं :—

### नियम

1. संक्षिप्त नाम.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, राज्य चुनाव आयुक्त (सेवा शर्त) नियम, 1994 है।  
(2) ये नियम तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) “अधिनियम” से हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 अभिप्रेत है;

(ख) “राज्य चुनाव आयुक्त” से भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-कं० और 243-जेड ए० के साथ पठित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 160 के अधीन नियुक्त राज्य चुनाव आयुक्त अभिप्रेत है;

(2) अन्य सब शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वे ही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके हैं।

3. वेतन.—राज्य चुनाव आयुक्त को, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन संयंत्र दिया जाएगा :

परन्तु यदि कोई व्यक्ति राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में पद ग्रहण की तारीख से पूर्व, राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन की गई पद सेवा के विषय में (निष्काशा या क्षति पैदा करने से अन्यथा) पेंशन प्राप्त कर रहा था या पेंशन हा प्राप्त है, और उसके पेंशन लेने का निर्धारण किया था, तो राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में सेवा के लिए उसके वेतन से निम्नलिखित घटाई जाएगी :—

(क) उनकी पेंशन की राशि ; और

(ख) यदि उसके पद ग्रहण करने से पूर्व, ऐसी पूर्व सेवा के आधार पर उसे वेतन पेंशन के धारक में पेंशन के भाग की राशि, जिस पर मार्गदर्शित मूल्य दिया गया है :

परन्तु यह और कि जब किसी व्यक्ति को राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में उस समय नियुक्त किया जाता है जबकि वह सरकारी सेवा में हो तो वह अधिभारिता की आयु पूरा करने पर सेवा निवृत्त होगा और उसके पश्चात् उसका वेतन पूर्ववर्ती उपयोगों के अनुसार कम किया जाएगा।

4. पद, शक्ति.—राज्य चुनाव आयुक्त अपने पद ग्रहण की तारीख से, शक्ति की शर्तों के लिए पद धारण करेगा :

परन्तु वह किसी भी समय राज्यपाल की दम्बोधित करने अपने हाथ से विन्य कर अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है।

5. अधिनियम.—(1) कोई व्यक्ति जो राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में पद ग्रहण करने की तारीख से पूर्व सरकारी सेवा में था जो उसकी प्रभावशक्ति के दौरान उस सेवा निवृत्ति के पूर्व तारीख से पूर्व सम्मानित है को तत्काल प्रयुक्त आयु नियमों के अनुसार अवकाश प्रदान किया जाएगा किन्तु उसके पश्चात् नहीं और वह ऐसी तारीख की अवधि में जहां अवकाश के अवकाश का इंतजार होगा।

(2) कोई व्यक्ति ऐसा व्यक्ति जो राज्य प्रशासन या पुलिस के काम में नियुक्त किया गया है, को ऐसे विधियों के अधीन आना प्रत्याक्ष किया जाएगा जो तत्समय विभाजन प्रदेश सरकार के अधीन-1 के अधिनियमों को लागू हों।

(ii) राज्य चुनाव आयोग को प्रकाश प्रसार करने, उसे आलोचक कार्यक्रम और प्रतिस्पर्धा करने या काम करने की शक्ति राज्यपाल में निहित होगी।

6. अन्वेषण के लक्षण में नगर भूगोल :- राज्य के नगर माबुसत, शिक्षा के प्रश्न सरकार के श्रेणी-1 के अधिकारी को सर्वेकार्य अन्वेषण के लक्षण में नगर भूगोल के अन्वेषण के लक्षण में नगर भूगोल का अन्वेषण होगा :

बशर्तु अथ कोई सेवा मिलन क्यविन राज्य सुनाय सायुक्त के म्बा में मियुक्त किया जाता है और उगने प्रपनी प्रप्रीयविदा के पबभात्, प्रबभाण को म्पयज में म्गद म्गताय प्रपि किया है, तो यह प्रबर्बाविता पर प्रबभाण के प्रबर्बा प्राप्त किए गए म्गताय और 240 दिनों के प्रबभाण के म्गताय का विवि कांई हो, ह्मयान होगा ।

7. सेवा की अन्य शर्तें—इन नियमों में अन्यथा उल्लिखित के विवादे, राज्य गुप्तता अधिनियम, अधिगण यात्रा विधायक या डिप्टी कमिश्नर सरकार के क्षेत्रों के अधिकारी को अनुमति है, बाह्य मूल्य प्राप्त नगरीय प्रशासन या अन्य स्थान पर 2,500 रुपये प्रतिमास, एवं कार्यालय में और दूसरा आवास स्थान पर दूरस्थ बुधियायें, प्रतिमास 400 रुपये की दर से सरकार तथा और नियुक्त बाह्य बुधिया प्राप्त करने का हवाला देना तथा अब वह सरकारी घरे पर हो तो यह विभाजन प्रवेश सरकार के क्षेत्रों के अधिकारियों का मिलने वाले प्रतिक्रिया शर्तों को प्राप्त करने की हवादार होगी। डिप्टी कमिश्नर प्रवेश सरकार के क्षेत्रों के अधिकारियों को समाप्त विविधता बुधियायें भी प्राप्त करने के हवादार होगी।

[illegible]

आनिदेश ४१५५.

ସ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସାବିତ୍ରୀ,

कृषि उत्पादन, आयुष्य एवं मजिद ।

[Authoritative English text of Government Notification No. PCH-IIA (4)-1/94, dated 17th December, 1994, as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

## RURAL DEVELOPMENT &amp; PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT

## NOTIFICATION

*Shimla-2, the 17th December, 1994*

No. PCH-HA (4)-1994. In exercise of the powers conferred by section 160 and 186 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (4 of 1994) read with clause (2) of Article 243-K and 243 ZA of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules entitled as the State Election Commissioner (Condition of Services) Rules, 1994, the same having been previously published in the Official Gazette : —

## RULES

1. *Short title.*—(1) These rules may be called the State Election Commissioner (Condition of Service) Rules, 1994.

(2) These rules shall come into force at once.

2. *Definitions.*—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) “Act” means the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994;

(b) “Governor” means the Governor of the State of Himachal Pradesh; and

(c) “State Election Commissioner” means the State Election Commissioner appointed under section 160 of the Himachal Pradesh Panchayat Raj Act, 1994 read with articles 243-K and 243-ZA of the Constitution of India.

(2) All other words and expressions used in these rules, but not defined herein, shall have the same meanings as are assigned to them in the Act.

3. *Salary.*—There shall be paid to the State Election Commissioner a salary which is equal to the salary of a Judge of the High Court:

Provided that if a person who, immediately before the date of assuming office as the State Election Commissioner, was in receipt of or, being eligible so to do, had elected to draw, a pension (other than a disability or wound pension) in respect of any previous service under the Government of the Union, his salary in respect of services as the State Election Commissioner shall be reduced:—

(a) by the amount of that pension; and

(b) if he had before assuming office, received, in lieu of a portion of the pension due to him in respect of such previous services the commuted value thereof, by the amount of that portion of the pension:

Provided further that when a person is appointed as State Election Commissioner while in service of the Government shall retire from service on attaining the age of superannuation and thereafter his salary shall be reduced in accordance with the foregoing proviso.

4. *Term of Office.*—The State Election Commissioner shall hold office for a term of five years from the date on which he assumes his office:

Provided that he may, at any time, by writing under his hand addressed to the Governor, resign his office.

5. *Leave.*—(1) A person who, immediately before the date of assuming office as the State Election Commissioner, was in service of Government, may be granted during his tenure of office but not thereafter, leave in accordance with the rules for the time being applicable to the service to which he belonged before such date and he shall be entitled to carry forward the amount of leave standing at his credit on such date.

(2) Any other person who is appointed as the State Election Commissioner may be granted leave in accordance with such rules as are for the time being applicable to a Grade-I Officer of the Himachal Pradesh Government,

(3) The power to grant or refuse leave to the State Election Commissioner and to revoke or curtail leave granted to him, shall vest in the Governor.

6. *Leave encashment.*—The State Election Commissioner shall be entitled for leave

encashment as admissible to a Grade-I Officer of the Himachal Pradesh Government :

Provided that when a retired person is appointed as the State Election Commissioner and has received leave encashment after his superannuation he shall be entitled for the difference, if any, between the leave encashment he received at the superannuation and 240 days.

7. *Other conditions of services.*—Save as otherwise provided in these rules, the State Election Commissioner shall also be entitled for Leave Travel Concession as per entitlement of a grade-I Officer of the State Government, rent free semi-furnished accommodation or Rs. 2,500/- per month in lieu thereof, telephone facility one in the office and another at residence, sumptuary allowance Rs. @ 400/- per month and free conveyance facilities and while on official tour entitled to get daily allowance as is admissible to a Grade-I Officer of the Himachal Pradesh Government.

8. *Re-appointment.*—The State Election Commissioner shall not be eligible for re-appointment on expiry of the term specified in rule 4 of these rules.

By order,

O. P. YADAV,  
*Agriculture Production Commissioner-cum-Secretary.*